

कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में लैंगिक बाधाओं का सामना कर रहा है राजस्थान

- पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी 10% पर रुकी हुई है
- अपने 30% आरक्षण लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजस्थान पुलिस को नियुक्त करनी होंगी 23,354 महिलाएं

15 नवंबर, 2023, राजस्थान: 2022 की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) देश में न्याय क्षमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग निर्धारित करने वाली एकमात्र रिपोर्ट है, जिसे इस साल की शुरुआत में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में देश के मध्यम एवं बड़े 18 राज्यों में राजस्थान 15वें स्थान पर है।

वर्ष 2008 से वर्ष 2021 के बीच कुछ सुधारों के बावजूद पुलिस एवं न्यायपालिका में रिक्तियों और विविधता से जुड़ी चुनौतियाँ प्रभावी न्याय वितरण के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं।

सुश्री माया दारुवाला, मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 ने कहा, “हम 2030 तक सभी के लिए न्यायिक संस्थानों को मजबूत बनाने के साथ-साथ न्याय की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे समय में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मौजूदा न्याय व्यवस्था, खास तौर पर पुलिस और न्यायपालिका की कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करती है। लंबे समय से बरकरार रही चुनौतियों के विषय पर एक व्यावहारिक विचार-विमर्श की शुरुआत करते हुए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की ये जानकारी, हमारी न्याय वितरण प्रणाली में तात्कालिक और मौलिक सुधारों की आवश्यकता को दोहराती हैं, जो आखिरकार एक न्यायसंगत और समान समाज की ओर मार्ग प्रशस्त करेंगी।”

साल 2008 के बाद से पुलिस रिक्तियों में तीन गुना बढ़ोतरी; 'सामान्य' श्रेणी की हिस्सेदारी ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी 10% पर रुकी हुई है

हालाँकि वर्ष 2008 से वर्ष 2021 के दौरान पुलिस बलों में स्वीकृत पदों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 78,033 से 1,10,949 हो गई है, और इसकी तुलना में रिक्तियों में भी बढ़ोतरी हुई है जो साल 2008 में 5,054 से तीन गुना बढ़कर साल 2021 में 15,412 हो गई हैं। कांस्टेबलों के रिक्त पदों की कुल संख्या अपेक्षाकृत कम, यानी 8% है। इसके विपरीत, अधिकारियों के बीच रिक्त पदों का प्रतिशत चिंताजनक रूप से 46% था – यह आंकड़ा वर्ष 2008 में 22% की तुलना में बढ़कर दोगुने से अधिक हो गया है।

इन रिक्तियों के अंतर्गत, वर्ष 2008 में 'सामान्य' श्रेणी के लिए रिक्तियां '0' थीं जो वर्ष 2021 में बढ़कर 10% हो गईं, और इस प्रकार अधिकारियों के 3,414 पद तथा कांस्टेबल के 2,076 पद रिक्त हैं। वर्ष 2008 में 'सामान्य' श्रेणी की कुल हिस्सेदारी 56% थी जो वर्ष 2021 में घटकर 51% हो गई है। वर्ष 2008 के बाद से 'सामान्य' श्रेणी की कुल हिस्सेदारी में लगातार गिरावट के बावजूद, राज्य की पुलिस बल में उनकी संख्या 50% से अधिक बनी हुई है। कुल पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 10% है,

जिसे देखते हुए राजस्थान पुलिस को अपने 30% आरक्षण लक्ष्य को पूरा करने के लिए 23,354 महिलाओं को नियुक्त करने की जरूरत है।

जातिगत विविधता एक चुनौती है, और अधिकारियों के कुल रिक्त पदों में **66%** रिक्तियाँ ओ.बी.सी के बीच केंद्रित हैं

पुलिस संगठनों पर नवीनतम डेटा (DOPO 2022) के अनुसार, पुलिस में ज्यादातर रिक्तियाँ ओ.बी.सी अधिकारियों के बीच केंद्रित हैं, जो 66% तक पहुंच चुका है और यह आंकड़ा सभी रैंकों और श्रेणियों में सबसे अधिक है। इसके बाद अनुसूचित जातियाँ (SC) 46% पर हैं। जाति विविधता में कुछ प्रगति के साक्षात्कार के रूप में, अनुसूचित जनजातियों (ST) के अधिकारियों में रिक्तियों में थोड़ी कमी आई है, जो 2008 में 47% से 2021 में 38% तक घट गई है।

कुल मिलाकर देखा जाए, तो एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधित्व में थोड़ा सुधार हुआ है, जबकि एससी की हिस्सेदारी स्थिर बनी हुई है। कांस्टेबल के पदों की बात की जाए, तो वर्ष 2012, 2013 और 2014 को छोड़कर, वर्ष 2008 से 2021 के दौरान एसटी के लिए कोटा लगातार पूरा किया गया है। इसके अलावा, कांस्टेबल के पदों पर ओबीसी की रिक्तियों में भी भारी गिरावट देखी गई है, जो इस अवधि में 43% से आधी होकर 24% रह गई है।

न्यायपालिका में रिक्तियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उच्च न्यायालय में कार्यरत **27** न्यायाधीशों में से केवल **2** महिलाएँ हैं

राज्य के अदालतों में रिक्तियों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में क्रमशः 16% और 45% रिक्तियों की तुलना में वर्तमान में यह आंकड़ा बढ़कर 20% और 48% तक पहुंच गया है। वर्ष 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान की अधीनस्थ अदालतों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 1,579 है, जिनमें से 317 पद रिक्त हैं। इनमें से ज्यादातर पद (196) एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी श्रेणियों के हैं, और शेष पद (121) 'सामान्य' श्रेणी के हैं। इन अदालतों में जातिगत श्रेणी के आधार पर ओ.बी.सी न्यायाधीशों की संख्या 25% है, जो की सबसे अधिक है। अधीनस्थ न्यायालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बेहतर हुआ है, जो वर्ष 2018 में 27% से बढ़कर वर्ष 2022 में 40% हो चुका है। हालाँकि, उच्च न्यायालय में कार्यरत 26 न्यायाधीशों में से केवल 2 महिलाएँ हैं।

नवीनतम जानकारी के अनुसार, राजस्थान में पुलिस, जेल और न्यायपालिका में रिक्त पदों की कुल संख्या 17,784 है।